भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2953

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं में हुई प्रगति

2953. श्री गणेश सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है और प्रथम चरण में प्रस्तावित और शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के संदर्भ में परिकल्पित निवेशों, लक्षित कोयला गैसीकरण क्षमता और संभावित परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड-भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सीआईएल-भेल) और कोल इंडिया लिमिटेड-गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएल-गेल) की संयुक्त उद्यम कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और चालू होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन से आयात पर भारत की निर्भरता को किस हद तक कम किए जाने की संभावना है जबकि घरेलू कोयला संसाधनों से ऊर्जा सुरक्षा और मूल्यवर्धन में वृद्धि होगी; और

(ङ) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रौद्योगिकी भागीदारी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): सरकार ने दिनांक 13.05.2026 को 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की स्कीम को मंजूरी दी।

स्कीम दिशानिर्देश दिनांक 25.06.2026 को जारी किए गए, जबकि आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध दिनांक 07.07.2026 को जारी किया गया है। आशा है कि इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 25 सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें लगभग 75 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कोयले का उपयोग किया जाएगा।

(ख): इससे पहले, सरकार ने दिनांक 24.01.2024 को 8,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की स्कीम को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के अंतर्गत आठ (8) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। परिकल्पित निवेश, उत्पादन क्षमता और अपेक्षित परिणामों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य**	**परियोजना/कंपनी**	**उत्पाद**	**उत्पादन क्षमता**	**निवेश (₹ करोड़)**
1	ओडिशा	भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)	अमोनियम नाइट्रेट	0.66 एमएमटीपीए	25,016
2		जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल)	डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)	2.0 एमएमटीपीए	3,882
3	पश्चिम बंगाल	कोल गैस इंडिया लिमिटेड (सीजीआईएल)	सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी)	633.6 मिलियन एनएम^3/वर्ष	13,053
4	महाराष्ट्र	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी)	633.6 मिलियन एनएम^3/वर्ष	12,215
5		ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड (जीईएमपीएल)	डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)	0.5 एमएमटीपीए	2,763
6		न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एनईसीएसपीएल)	अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन	0.33 एमएमटीपीए एएन + 0.10 एमएमटीपीए H_2	6,976
7		न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एनईसीएसपीएल)	एथनॉल	18 केटीपीए	667

8		कार्तिकेय वायुनंदन प्राइवेट लिमिटेड (केवीपीएल)	एसिटिक एसिड	75.9 केटीपीए	793

इन 8 परियोजनाओं से लगभग 12 एमएमटीपीए कोयले को गैसीकृत करने और लगभग 65,365 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की अपेक्षा है।

(ग) : दो संयुक्त उद्यम कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है -

(i) **भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)** सीआईएल और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम, यह परियोजना अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए लखनपुर, ओडिशा में स्थित है। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, ईपीसी अनुबंध प्रदान किए जा चुके हैं, और दिनांक 20.06.2026 को ग्राउंड-ब्रेकिंग पूरी हो गई। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2030 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) **कोल गैस इंडिया लिमिटेड (सीजीआईएल)** सीआईएल और गेल का एक संयुक्त उद्यम, यह परियोजना सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) के उत्पादन के लिए बर्धमान, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह परियोजना पूर्व-निर्माण चरण में है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) प्राप्त कर लिए गए हैं और प्रमुख पैकेजों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2030 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन से वर्ष 2030 तक 100 मि.ट. कोयले को गैसीकृत किए जाने की संभावना है ताकि आयात निर्भरता को कम किया जा सके, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके और उर्वरक, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन आदि जैसे ईंधनों और रसायनों का उत्पादन किया जा सके। 8,500 करोड़ रुपये की स्कीम, 37,500 करोड़ रुपये की स्कीम और तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तहत परियोजनाओं को चालू होने पर, कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक आयात प्रतिस्थापन होने की अपेक्षा है।

(ड.): जनवरी 2024 में स्वीकृत कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन स्कीम में, निजी कंपनियां श्रेणी II (कुल परिव्यय 3,850 करोड़ रुपये) और श्रेणी III (कुल परिव्यय 600 करोड़ रुपये) में वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकती हैं। मई 2026 में स्वीकृत नई स्कीम में निजी क्षेत्र की कंपनियां वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

जनवरी 2024 में अधिसूचित स्कीम की श्रेणी- III में, स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित डेमंसट्रेशन परियोजनाओं का समर्थन किया गया है। श्रेणी-I के अंतर्गत भारत कोल

गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) भेल द्वारा विकसित स्वदेशी गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित है। श्रेणी-II के तहत, जिंदल स्टील लिमिटेड ने नलवा ग्रीन एनर्जी के स्वामित्व वाली लुर्गी गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

मई 2026 में स्वीकृत स्कीम में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।

कोयला मंत्रालय अवसंरचना इष्टतमीकरण को सक्षम करने के लिए क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण सहित कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कोयला उत्पादक राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। ओडिशा, महाराष्ट्र आदि राज्यों ने अपने राज्यों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाई हैं।

****